[2022] 3 एस.सी.आर.

राजेश प्रसाद

बनाम्

बिहार राज्य और एक अन्य आदि

(आपराधिक अपील सं. 2015 का 111-113)

7 जनवरी, 2022

[एल. नागेश्वर राव, बी. आर. गवई और

बी. वी. नागरत्ना, न्यायमूर्तिगण]

दंड संहिता, 1860 : धाराएँ302/34, 120B - विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 - धाराएँ 3,4 - वर्तमान मामले में, अभियुक्त-प्रत्यर्थी ने अपीलकर्ता-सूचना देने वाले के पिता और अन्य मृत पीड़ित की विस्फोटक पदार्थ (बम) के उपयोग से मृत्यु कारित कर आई. पी. सी. की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 और धारा 120 बी के तहत अपराध किया और इस तरह विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3/4 के तहत भी आरोप लगाया गया - मुकदमे में, अभियुक्त को दोषी ठहराया गया और कारावास की अवधि के साथ मौत की सजा भी दी गई - उच्च न्यायालय ने उसे इस आधार पर सभी आरोपों से बरी कर दिया कि जांच में खामियां थीं और अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में भी - अभियुक्त को बरी करते हुए, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा झूठी गवाही के अपराध के लिए उस पर मुकदमा चलाने का निर्देश दिया - इसलिए प्रतिवादी के दोषसिद्धि निरस्त करने के खिलाफ एवं झूठी गवाही के विरूद्ध प्रक्रिया शुरु करने के खिलाफ वर्तमान अपील अवधारितः विचारण न्यायालय अभियोजन गवाह 1,3,4 और 7 के साक्ष्य की उचित परिप्रेक्ष्य में सराहना करने में विफल रहा और आगे इस तथ्य को पहचानने में विफल रहा कि पी. डब्ल्यू.-7 (अपीलार्थी) ने अभियोजन पक्ष के मामले का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया, हालांकि वह सूचनादाता और इसलिए, गलती से अभियुक्त को दोषी ठहराया - हालाँकि, इन मामलों के तथ्यों और

परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और यह ध्यान में रखते हुए कि घटना में दो मौतें हुई थीं जो उचित संदेह से परे साबित नहीं हुई थीं, केवल अपीलार्थी के खिलाफ झूठी गवाही की कार्यवाही शुरू करने के लिए विचारण न्यायालय के निर्देश को निरस्त कर दिया जाता है - बरी करने के बाकी आक्षेपित निर्णय की पुष्टि की जाती है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – की धारा 378 - शक्ति और दायरा - अपीलीय न्यायालय को बरी किए जाने के फैसले की समीक्षा करने और उसे उलटने की पूरी शक्तियां हैं-उच्च न्यायालय को साक्ष्य पर एक अलग दृष्टिकोण रखने के लिए यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त और बाध्यकारी कारण भी होने चाहिए कि निचली अदालत गलत थी - उच्च न्यायालय को बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर विचार करते समय सतर्क रहना चाहिए क्योंकि अभियुक्त के पक्ष में निर्दोष होने की धारणा इस तथ्य से कमजोर नहीं होती है कि उसे उसके मुकदमे में बरी कर दिया गया है, लेकिन यदि अदालत अन्यथा मानती है तो उसे बरी किए जाने के फैसले से असहमत होने के कारण बताए जाने चाहिए।

अपील - उच्चतम न्यायालय का आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार-बरी किए जाने के खिलाफ अपील के मामलों में विस्तार और गुंजाइश-उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के आदेश की पुष्टि किए जाने वाले मामलों में ऐसी शक्ति का प्रयोग दुर्लभ है - ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब उच्च न्यायालय का निष्कर्ष बिल्कुल गलत, विधिक रूप से गलत और मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विकृत हो।

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने निर्धारित किया:

1. यह केवल दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में है, जहां उच्च न्यायालय ने तर्क की पूरी तरह से गलत प्रक्रिया और मामले के तथ्यों के लिए कानूनी रूप से गलत और विकृत दृष्टिकोण पर, कुछ सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी करते हुए, आरोपी को बरी कर दिया है, कि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा इसे उलट दिया जा सकता है।इस तरह के बंधन जो एक अपील पर विचार करने का अधिकार किसी व्यक्ति को अनावृत करने की अनिच्छा से प्रेरित होकर, एक अपील पर विचार करने के लिए किसी व्यक्ति को, जिसे एक सक्षम अदालत द्वारा आपराधिक आरोप से बरी कर दिया गया है,

मामले की आगे की जांच की चिंता और तनाव के लिए बेनकाब करने की अनिच्छा से प्रेरित किया जाता है, भले ही यह एक उच्चतर न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया हो।बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ एक अपील पर विचार नहीं किया जा सकता है, जो वैध और महत्वपूर्ण कारणों को दर्ज करने के बाद अकाट्य तार्किक निष्कर्ष जो आया है, बरी होने को उचित ठहराता है।[पैरा 30] [1063-डी-जी]

2. जिन परिस्थितियों में यह न्यायालय दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील पर विचार कर दोषसिद्धि का आदेश पारित कर सकता है, उसका सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैः (i) जहाँ उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण या तर्क विकृत हैः (ए) जहां उच्च न्यायालय द्वारा संदेह और अनुमानों के आधार पर निर्विवाद साक्ष्य को खारिज कर दिया गया है, जो कि यद्यपि अवास्तविक हैं। (बी) जहाँ पीड़ित के साथ एक ही घर में रहने वाले रिश्तेदारों की गवाही के गुणावगणों को इस आधार पर छूट दी गई थी कि वे 'इच्छुक' गवाह थे। (सी) जहां उच्च न्यायालय द्वारा गवाहों की गवाही पर विश्वास नहीं किया गया था, गवाहों की ओर से अभियुक्त को फंसाने के व्यक्तिगत उद्देश्य के अवास्तविक अनुमान पर, जबकि वास्तव में, गवाहों के पास उक्त मामले में अव्यक्त प्रयोजन या स्वार्थी उद्येश्य नहीं थी। (डी) जहाँ उच्च न्यायालय द्वारा पीड़ित मृतक की मृत्यु घोषणा को अप्रासंगिक आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उन्होंने घटना के स्थान पर मौजूद व्यक्तियों में से एक पर पाई गई चोट की व्याख्या नहीं की थी। (ई) जहाँ उच्च न्यायालय ने 'उचित संदेह से परे प्रमाण' के बजाय 'अंतर्निहित प्रमाण' का अवास्तविक मानक लागू किया और इसलिए साक्ष्य का त्रुटिपूर्ण तरीके से मूल्यांकन किया। (एफ) जहाँ उच्च न्यायालय ने एक अतिशयोक्तिपूर्ण और मनमौजी सिद्धांत पर आधारित परिस्थितिजन्य साक्ष्य, जो अभियुक्त की याचिका से परे थे या जहां बरी होना केवल अभियुक्त के पक्ष में संदेह के लाभ के नियम के प्रति अतिरंजित समर्पण में निहित है को अस्वीकार कर दिया हो। (जी) जहाँ उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को इस आधार पर बरी कर दिया कि उसके पास नहीं था-अपराध करने के लिए पर्याप्त उद्देश्य नहीं था-हालांकि, उक्त मामले में, अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने वाले मजबूत प्रत्यक्ष साक्ष्य थे, जिससे इसे अभियोजन ओर से 'उद्देश्य' स्थापित करने के लिए अनावश्यक बना दिया गया। (ii) जहां बरी होने का परिणाम न्याय का घोर विफलता होगा (ए) जहां उच्च न्यायालय के निष्कर्ष, अभियुक्त व्यक्तियों को

अपराध से अलग करते हुए, साक्ष्य असावधानीपूर्वक विचार पर आधारित थे या विस्तार करने वाली परिस्थितियों पर आधारित थे जो विशुद्ध रूप से कल्पना एवं मनोरंजन पर आधारित थेः (बी) जहां अभियुक्त को मुकदमे के संचालन में देरी के आधार पर बरी कर दिया गया था, जो देरी अभियोजन एजेंसियों की देरी या उदासीनता के कारण नहीं थी, बल्कि स्वयं अभियुक्त के आचरण के कारण थी; या जहां अभियुक्त को किसी ऐसे अपराध से संबंधित मुकदमे के संचालन में देरी के आधार पर बरी कर दिया गया था जो तुच्छ प्रकृति का नहीं है।[पैरा 30] [1064-ए-एच; 1065-ए-एफ]

> उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सतीश सहाय ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 1442; अरुणाचलम बनाम साधनंदन ए. आई. आर. 1979 (एस. सी.) 1284:[1979] 3 एस. सी. आर. 482; हरियाणा राज्य बनाम लखबीर सिंह (1990) सी. आर. एल. जे. 2274 (एस. सी.); राजस्थान राज्य बनाम सुखपाल सिंह, ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 207:[1983] 2 एस. सी. आर. 53; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम शंकर, ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 879; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हकीम सिंह ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 184; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रांझा राम, ए. आई. आर. 1986 एस. सी. 1959; महाराष्ट्र राज्य बनाम चंपालाल पुंजाजी शाह, ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 1675; गुरबचन बनाम सत्यपाल सिंह, ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 209:1989 (1) पूरक एस. सी. आर. 292; आंध्र प्रदेश राज्य बनाम बोगम चंद्रैया, ए. आई. आर. 1986 एस. सी. 1899; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम फेरू सिंह, ए. आई. आर. 1989 एस. सी. 1205 और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पुसू 1983 ए. आई. आर. 867 (एस. सी.):[1983] 3 एस. सी. आर. 294-पर निर्भर था।

3. उच्च न्यायालय ने मामले की जांच और अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में खामियों को भी नोट किया जिन्हें निम्नानुसार निकाला गया हैः(i) पीडब्लू-7 ने कहा कि पीडब्लू-4 ने लिखित रिपोर्ट तैयार की, जबकि पीडब्लू-4 ने इससे इनकार किया। (ii) जबकि पीडब्लू-1 और पीडब्लू-3 मृतक से संबंधित थे और घटना के तुरंत बाद जब्ती सूची पर

हस्ताक्षर किए थे, फिर भी पीडब्लू-3 ने कहा था कि वह जब्ती सूची के अन्य हस्ताक्षरकर्ता के बारे में नहीं जानता था। (iii) पी. डब्ल्यू.-1 का बयान, जो जब्ती सूची का गवाह होने के साथ-साथ एक चश्मदीद गवाह भी था, डेढ़ महीने बाद पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें गवाह या पुलिस द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। (iv) इसी तरह, पीडब्लू-4 का बयान जो एक चश्मदीद गवाह है और मृतक की जांच रिपोर्ट का गवाह है और जिसके बारे में कहा गया है कि पुलिस को दी गई लिखित रिपोर्ट तैयार की, जिसे पुलिस ने दो महीने और बीस दिनों के बाद दर्ज किया। उच्च न्यायालय ने कहा है कि देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है, हालांकि यह माना जा सकता है कि जब लिखित रिपोर्ट पुलिस को सौंपी गई थी तो वह पुलिस स्टेशन में मौजूद थे।(v) मृतक की पान की दुकान से सटे पी. सी. ओ. बूथ का दुकान मालिक पी. डब्ल्यू.-2 भी घटना के दौरान कथित रूप से घायल हो गया था, लेकिन कोई चोट की रिपोर्ट नहीं है।(vi) जबकि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने तीन या अधिक बम फेंकने का आरोप लगाया, जांच अधिकारी ने कहा कि उन्हें केवल दो विस्फोटों के संकेत मिले; पहला मृतक की पान की दुकान पर और दूसरा मैसर्स आदित्य इलेक्ट्रॉनिक्स के पास, जो पहले विस्फोट स्थल के उत्तर में 40-45 गज की दूरी पर स्थित है। [पैरा 52] [1077-सी-एच; 1078-ए-सी]

4. फास्ट ट्रैक कोर्ट अभियोजन गवाह 1,2,3,4 और 7 का साक्ष्य उचित परिप्रेक्ष्य में सराहना करने में विफल रहा है और आगे इस तथ्य को पहचानने में विफल रहा है कि पीडब्लू-7/अपीलार्थी ने अभियोजन पक्ष के मामले का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया, हालांकि वह मुखबिर था और इसलिए, गलती से आरोपी को दोषी ठहराया और उनमें से दो को मौत की सजा और तीसरे आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।इसलिए, उच्च न्यायालय को फास्ट-ट्रैक न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश को उलटने में उचित ठहराया गया।इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने कहा कि यह अपीलार्थी के खिलाफ झूठी गवाही की कार्यवाही शुरू करने के लिए एक उपयुक्त मामला है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलकर्ता, जो सूचनादाता था, ने मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के मामले का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया और परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने आरोपी को बरी कर दिया।तथापि, इन मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यह ध्यान में रखते हुए कि 10 मार्च, 2005 को हुई घटना में दो मौतें हुई थीं, जो उचित संदेह से परे साबित नहीं हुई हैं,

आक्षेपित निर्णय और आदेश के उस भाग को खारिज कर दिया जाता है जिसमें निचली अदालत को अपीलार्थी के खिलाफ झूठी गवाही की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया था। [पारस 54,57,58] [1080-ए-बी, डी-एफ]

एटली बनाम यु.पी. राज्य की स्थिति ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 807; संवत सिंह बनाम राजस्थान राज्य ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 715:[1961] 3 एस. सी. आर. 120; अहेर राजा खीमा बनाम सौराष्ट्र राज्य ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 217:[1955] 2 एससीआर 1285; एम.जी. अग्रवाल बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए. आई. आर 1963 एस. सी. 200:[1963] 2 एस. सी. आर. 405; शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य (1973) 2 एससीसी 793:[1974] 1 एससीआर 489; रमेश बाबूलाल दोशी बनाम गुजरात राज्य (1996) 9 एससीसी 225:[1996] 2 पूरक।एस. सी. आर. 265; अजीत सावंत मजगवाई बनाम कर्नाटक राज्य (1997) 7 एस. सी. सी. 110:[1997] 3 पूरक। एससीआर 444; रमेश बाबूलाल दोशी बनाम गुजरात राज्य, (1996) 9 एससीसी 225:[1996] 2 पूरक।एस. सी. आर. 265; चंद्रप्पा और अन्य बनामकर्नाटक राज्य (2007) 4 एस. सी. सी. 415:[2007] 2 एससीआर 630; नेपाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2009) 12 एससीसी 351:[2009] 6 एससीआर 982-पर निर्भर था।

मामला कानून संदर्भ

ए आई आर 1934 पी. सी. 227 (2)	पर आधारित	कंडिका 20
ए आई आर 1955 एससी 807	पर आधारित	कंडिका 21
[1961] 3 एससीआर 120	पर आधारित	कंडिका 21
[1955] 2 एससीआर 1285	पर आधारित	कंडिका 21
[1963] 2 एससीआर 405	पर आधारित	कंडिका 22

[1974] 1 एससीआर 489	पर आधारित	कंडिका 23
[1996] 2 पूरक एल सी आर 265	पर आधारित	कंडिका 24
[1997] 3 पूरक एस सी आर 444	पर आधारित	कंडिका 25
[1996] 2 पूरक एस सी आर 265	पर आधारित	कंडिका 26
[2007] 2 एससीआर 630	पर आधारित	कंडिका 27
[2009] 6 एससीआर 982	पर आधारित	कंडिका 29
ए. आई. आर 1981 एस. सी. 1442	पर आधारित	कंडिका 30(ए)
[1979] 3 एससीआर 482	पर आधारित	कंडिका 30(ए)
(1990) सीआरएलजे 2274 (एससी)	पर आधारित	कंडिका 30(ए)
[1983] 2 एससीआर 53	पर आधारित	कंडिका 30(बी)(i)(ए)
ए. आई. आर 1981 एस. सी 879	पर आधारित	कंडिका 30(बी)(i)(ए)
ए. आई. आर एस. सी 184	पर आधारित	कंडिका30(बी)(i)(बी)
[1983] 2 एससीआर 53	पर आधारित	कंडिका30(बी)(i)(सी)
[1979] 3 एससीआर 482	पर आधारित	कंडिका30(बी)(i)(डी)
आकाशवाणी 1986 एससी 1959	पर आधारित	कंडिका 30(बी)(i)(ई)
ए. आई. आर 1981 एस. सी 1675	पर आधारित	कंडिका30(बी)(i)(एफ)

[1989] (1) पूरक एस. सी. आर. 292 (एफ)	पर आधारित	कंडिका	30(बी)(i)
ए आई आर 1986 एससी 1899 (एफ)	पर आधारित	कंडिका	30(बी)(i)
ए. आई. आर 1989 एस. सी 1205 (ए)	पर आधारित	कंडिका	30(बी)(ii)
[1983] 3 एससीआर 294 (ए)	पर आधारित	कंडिका	30(बी)(ii)
[1982] 1 एससीआर 299 (ए)	पर आधारित	कंडिका	30(बी)(ii)

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयःआपराधिक अपील सं. 111-113/2015

2008 के आपराधिक अपील (खं. पी.) संख्यायें, 714,747 और 814 में पटना में उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 05.08.2009 से।

सुश्री प्रेरणा सिंह, टी. महिपाल, अधिवक्ता, अपीलार्थी के लिए।

साकेत सिंह, श्रीमती निरंजना सिंह, रंजन मुखर्जी, अधिवक्ता,उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय नागरथ्न, न्यायमूर्ति द्वारा दिया गया था।

निर्णय

नागरथ्न, न्यायमूर्ति

1. ये अपील अपीलार्थी सूचक (पी डब्लू 7 राजेश प्रसाद) द्वारा आपराधिक अपील संख्या 714,747 और 2008 के 814 में पटना में न्यायिक उच्च क्षेत्राधिकार द्वारा 5 अगस्त, 2009 को पारित निर्णय और आदेश पर हमला करते हुए दायर की गई है, जिसके

द्वारा 26 जून, 2008 को दोषसिद्धि का निर्णय और अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, पंचम, मुंगेर द्वारा 30 जून, 2008 को पारित दंड के आदेश को उपर्युक्त अपीलों को मंजूर करके और तदनुसार मृत्यु संदर्भ संख्या 13/2008 का जवाब देकर रद्द कर दिया गया है और परिणामस्वरूप सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है।

2. अपर जिला और सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, मुंगेर की अदालत ने अपने 26 जून, 2008 के फैसले के माध्यम से इसमें प्रत्यर्थियों को दोषी ठहराया। 30 जून, 2021 के आदेश द्वारा, त्वरित न्यायालय ने उपेंद्र राम को 5000/- रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना न देने की स्थिति में उसे भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में, 'आईपीसी') की धारा 120 बी के साथ पठित धारा 302/34 के तहत अपराध के लिए एक साल का कठोर कारावास भुगतना पड़ा और भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के तहत अपराध के लिए एक साल का कठोर कारावास भी भुगतना पड़ा और इसके बाद विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3/4 के तहत अपराध के लिए प्रत्येक को 10 साल के लिए कठोर कारावास भुगतना पड़ा और आदेश दिया कि दंडादेश समवर्ती रूप से चलाए जाएं।त्वरित न्यायालय ने अभियुक्तों को सजा सुनाई।भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के साथ पठित धारा 302/34 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3/4 के तहत मुन्ना राम और महेंद्र राम को मौत की सजा दी गई थी, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी।हालांकि त्वरित न्यायालय ने अन्य अभियुक्तों को बरी कर दिया।, फैंटस मंडल, धप्पू राम और चंद्रभानु प्रसाद शामिल थे।

3. यह अभियोजन का मामला है कि गुरुवार, 10 मार्च, 2005 को लगभग 5.00 बजे, महेंद्र राम, उपेंद्र राम, मुन्ना राम, धप्पू राम, सभी किशोरी राम और चंद्रभानु प्रसाद के पुत्र हैं, दो अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ मुखबिर की ओर बढ़े। राजेश प्रसाद (पी डब्लू और पी डब्लू और पी डब्लू और पी डब्लू 7) ने विरोध किया कि क्योंकि सूचक ने उनकी अवैध गतिविधियों का विरोध किया था, इसलिए उनके पूरे परिवार को एक बम से उड़ा दिया जाएगा। आरोपी मुन्ना राम ने सूचक के पिता छोटे लाल महतो पर बम फेंका, जो अपनी पान की दुकान में बैठे थे।उसके पिता के सिर का पिछला हिस्सा उड़ गया जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी महेंद्र राम ने ओ. पी. वर्मा पर एक और बम फेंका और इसके परिणामस्वरूप उसका सिर फट

गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा, उपेंद्र राम ने एक और बम फेंका, जो किसी को घायल करने से चूक गया और सड़क पर फट गया। तब आरोपी चंद्रभानु और दप्पू राम ने कहा कि वे वहां से आगे बढ़ेंगे क्योंकि उनका काम पूरा हो गया था और उन्होंने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए लोगों ने एक अज्ञात व्यक्ति को पकड़ लिया और उस पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। आरोपियों ने भागते हुए धमकी दी कि उनके द्वारा शराब की अवैध बिक्री के खिलाफ सूचक के विरोध का परिणाम है और अगर किसी ने भी उनके काम में बाधा डाली, तो उन्हें भी उसी तरह के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आरोपी चंद्रभानु प्रसाद ने आरोपी मुन्ना राम को मौके से भागने में मदद की।

4. सूचक ने आगे कहा था कि वह आरोपियों द्वारा शराब की अवैध बिक्री पर और दुश्मनी के कारण और उनके समान इरादे और उद्देश्य के अनुसरण में, उन्होंने बम फेंके थे और मुखबिर के पिता के साथ-साथ अन्य लोगों को मार डाला था।

5. कथित जानकारी प्राप्त होने पर, कोतवाली थाना में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34,120 बी और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (जिसे इसमें इसके बाद 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 3/4 के तहत 10 मार्च, 2005 को मामला संख्या 136/2005 दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की जांच की और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मुंगेर की अदालत के समक्ष 7 जून, 2005 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिसने भारतीय दंड संहिता की धारा 302,120 बी, 504,225 और अधिनियम की धारा 3/4 के तहत अपराधों के लिए अन्य आरोपों के संबंध में संज्ञान लिए। दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में, 'दं. प्र. सं.'), दिनांक 17 जून, 2005 के आदेश द्वारा।

6. यह मामला 9 दिसम्बर, 2005 को अपर जिला न्यायाधीश, मुंगेर के न्यायालय और बाद में त्वरित न्यायालय को अंतरित कर दिया गया। इसके बाद, संबंधित अपराधों के लिए आरोप को पढ़ा गया और अभियुक्तों को हिंदी में समझाया गया, जिसके लिए उन्होंने निर्दोष होने का अभिवचन किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

7. अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर दस गवाहों से पूछताछ की और सामग्री वस्तुओं (एमओ) पर ध्यान दिया। इसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत आरोपी के बयान दर्ज किए गए।सभी आरोपियों ने कथित घटना से इनकार किया और कहा कि वे निर्दोष हैं और उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि अशोक यादव द्वारा एक अवैध शराब की दुकान चलाने वाले सूचक से ली गई शराब के संबंध में बकाया था। अशोक यादव से कथित बकाया राशि की मांग की गई थी जिसके लिए उनके और सूचक के परिवार के बीच झगड़ा हुआ था और अशोक यादव पर हमला किया गया था। नतीजतन, कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने गुस्से में आकर बम फेंके और कथित घटना को अंजाम दिया कि मुखबिर के सहयोगियों आरोपी धप्पू राम की चाय की दुकान को लूटा और कहा कि मुखबिर ने आरोपी को गलत तरीके से फंसाया है।

8. हमने सुश्री प्रेरणा सिंह, अपीलार्थी के विद्वान वकील, श्री साकेत सिंह, राज्य के विद्वान वकील और श्री रंजन मुखर्जी, प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील, अभियुक्त के विद्वान वकील को सुना है और अभिलेख पर सामग्री का अवलोकन किया है।

9. अपीलार्थी के वकील ने प्रस्तुत किया कि त्वरित न्यायालय द्वारा दिए गए दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय को अपास्त करने में उच्च न्यायालय सही नहीं था और इस प्रकार अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया। उसने हमारा ध्यान पी डब्लू ३, ४, ५, ८, ९ और १० के साक्ष्य की ओर आकर्षित किया और प्रतिवाद किया कि यह स्पष्ट रूप से अभियुक्त के दोष को उचित संदेह से परे स्थापित करेगा। हालांकि, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के मामले की अपने उचित परिप्रेक्ष्य में सराहना नहीं की है और फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। अपीलार्थी ने पी डब्लू-7, जो मृतक छोटे लाल महतो के बेटों में से एक है, शिकायत में और अपने बयान में भी स्पष्ट रूप से कहा था कि अभियुक्त की संलिप्तता का उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया है।

10. अभिलेख पर साक्ष्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए, अपीलार्थी के विद्वत वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय गलत निष्कर्षों पर पहुंचा है और इस प्रकार त्वरित न्यायालय के निर्णय को पलट दिया है।

11. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने आगे प्रतिवाद किया कि अभियुक्त को दोषमुक्त करते समय, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि अपीलार्थी के खिलाफ झूठी गवाही की कार्यवाही शुरू की जाए, जो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि त्वरित न्यायालय ने अभियोजन का मामला स्वीकार कर लिया था और इसमें अपीलार्थी के साथ-साथ अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराया था, पूरी तरह से अनावश्यक था।

12. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने अंततः प्रतिवाद किया कि दोषमुक्ति के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जा सकता है और त्वरित न्यायालय का निर्णय बहाल किया जा सकता है क्योंकि अभियुक्तों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के साथ-साथ अन्य धाराओं के तहत गंभीर अपराध किया है जिसके परिणामस्वरूप दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, एक अपीलार्थी का पिता है और दूसरा मृतक के खिलाफ आरोपी द्वारा फेंके गए बम के कारण। उसने प्रस्तुत किया कि तीसरा बम जो एक आरोपी द्वारा फेंका गया था वह किसी व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचा सका, लेकिन इससे किसी भी तरह से उसे बरी नहीं किया जा सकता था।

13. दूसरी तरफ प्रतिवादी के विद्वत अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया और प्रतिवाद किया कि उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य को उचित रूप से समझा है और उसका मूल्यांकन किया है और इसके परिणामस्वरूप त्वरित न्यायालय के गलत निर्णय को उलट दिया है।यह प्रस्तुत किया गया कि त्वरित प्रक्रिया न्यायालय यह नोट करने में विफल रहा कि अभिलेख पर साक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध उचित संदेह से परे अभियोजन के मामले को साबित नहीं करता है और इसके बावजूद दो अभियुक्तों पर मृत्युदंड और एक अन्य अभियुक्त पर आजीवन कारावास अधिरोपित किया गया था जिसे उच्च न्यायालय द्वारा एक तर्कसंगत निर्णय द्वारा उचित रूप से उलट दिया गया है.इसलिए, आक्षेपित निर्णय इस न्यायालय के हाथों किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करेगा क्योंकि इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं है.इसलिए, अपील को खारिज किया जा सकता है।

14. संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमारे विचार के लिए निम्नलिखित मुद्दे उठेंगेः

(क) क्या त्वरित न्यायालय द्वारा दिए गए दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय को पलटने में उच्च न्यायालय न्यायोचित था, जिससे सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त किया गया?

(ख) क्या उच्च न्यायालय का निर्णय इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप या उपांतरण की मांग करता है?

(ग) कौनसा आदेश?

15. त्वरित न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मामले पर विचार किया क्योंकि 10 मार्च, 2005 को लगभग शाम 5 बजे आरोपी मुखबिर के पास आया और कहा कि चूंकि सूचक और उसके परिवार को देशी शराब की उसकी अवैध बिक्री पर आपत्ति थी, इसलिए वह अपने परिवार के साथ समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद आरोपी मुन्ना राम ने अपने हाथ में एक बम फेंका और पान की दुकान पर बैठे मुखबिर के पिता छोटे लाल महतो की विस्फोट में मौत हो गई।दूसरा बम आरोपी महेंद्र राम ने फेंका था जिससे ओ. पी. वर्मा नामक एक पैदल यात्री की मौत हो गई थी और तीसरा बम आरोपी उपेंद्र राम द्वारा फेंका गया था, जो सड़क पर फट गया था।इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। कि अपराधी द्वारा अपराध मृतक छोटे लाल महतो और उसके पुत्र पीडब्लू-7 राजेश प्रसाद सूचक- जो इसमें अपीलार्थी है, द्वारा अभियुक्त के अवैध शराब के व्यापार के खिलाफ उठाई गई आपत्ति के परिणामस्वरूप किए गए थे।

16. त्वरित न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि प्रतिरक्षा पक्ष अपने मामले को साबित करने में असमर्थ था कि अभियुक्त धप्पू राम की चाय की दुकान को मुखबिर और उसके सहयोगियों ने लूट लिया था। उन्होंने आगे कहा कि अशोक यादव द्वारा शराब की कीमतों के भुगतान के संबंध में विवाद था और इसके परिणामस्वरूप बाद में और उसके सहयोगियों ने बम विस्फोट किया था।

17. पीडब्लू-1,2,3 और 4 के बयान जो चश्मदीद गवाह थे और साथ ही पीडब्लू-7 यानी मुखबिर को त्वरित न्यायालय द्वारा एक-दूसरे के साथ संगत होने के रूप में स्वीकार किया गया था क्योंकि उनकी ऑकुलर गवाही ने अभियोजन पक्ष को किसी भी उचित संदेह से परे साबित किया था। तदनुसार, तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया और उपर्युक्त उल्लेख के अनुसार उन्हें सजा सुनाई गई।

18. त्वरित न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करने पर निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया और निम्नलिखित निष्कर्ष निकालाः

(i) कि पी डब्लू विलेन 1, पी डब्लू विलेन 3, पी डब्लू 4 और पी डब्लू 7 एक दूसरे से संबंधित हैं, वे क्रमशः मृतक, छोटे लाल महतो के चचेरे भाई और बेटे हैं। पी डब्ल्यू-2 पीसीओ बूथ का दुकानदार है जो सूचक की पान की दुकान के बगल में स्थित है। पी. डब्लू. 2 भी बम के एक टुकड़े से घायल हो गया, जो मृतक छोटे लाल महतो पर फेंका गया था, जो उसकी पान की दुकान में था। पीडब्लू-8 ने भी इस घटना को देखा। इस प्रकार, पीडब्ल्यू 2 पीडब्ल्यू 8 स्वतंत्र गवाह हैं। पी डब्लू 5 वह डॉक्टर है जिसने मृतक का पोस्टमार्टम किया और पी डब्लू 9 और 10 मामले के जांच अधिकारी (आईओ) हैं।

(ii) छोटेलाल महतो और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई और तीसरा बम सड़क पर फट गया। नतीजतन, जनता आक्रोशित हो गई और एक अज्ञात व्यक्ति को पकड़ लिया और उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। यह सबूत में आया था कि कथित व्यक्ति अशोक यादव था।

(iii) कि प्रथम इतला रिपोर्ट में फैंटस उर्फ उदय प्रकाश मंडल का नाम नहीं पाया गया था और गवाहों ने घटना में उसकी संलिप्तता के खिलाफ गवाही नहीं दी थी और न ही उसके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष कार्य किया गया था।

(iv) धप्पू राम और चंद्रभानु प्रसाद के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं की गई थी।

(v) नतीजतन, फैंटस मंडल, धप्पू राम और चंद्रभानु प्रसाद को किसी भी कथित अपराध का दोषी नहीं पाया गया और उन्हें बरी कर दिया गया।

(vi) अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करते हुए, यह पाया गया कि उपेंद्र राम, मुन्ना राम और महेंद्र राम दोषी थे और उन्हें त्वरित न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई।

19. अभियुक्त द्वारा दायर अपीलों में और मृत्यु निर्देश संख्या 13/2008 में, उच्च न्यायालय ने, अभियुक्त और राज्य की ओर से की गई प्रस्तुतियों पर विचार करने पर, आरंभ में निम्नलिखित रूप में नोट किया:

> "यह सामान्य विधि है कि सह अभियुक्त को दोषमुक्त करना अन्य अभियुक्तों को दोषमुक्त करने का आधार नहीं हो सकता। दोनों मामलों को अलग करने वाले कारक हो सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, एक गलत बरी और किसी चुनौती की अनुपस्थिति दूसरों द्वारा समान व्यवहार की मांग करने का आधार नहीं हो सकता है। इसी प्रकार, किसी हितबद्ध साक्षी की गवाही को केवल उसी आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता है। इसके लिए न्यायालय से केवल यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अधिक सतर्क रहे और साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच करे। साक्ष्य, अन्यथा ठोस और विश्वसनीय को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि कोई स्वतंत्रता गवाह नहीं था, हालांकि घटना एक व्यस्त सड़क पर हुई थी। किंतु ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां साक्षी हितबद्ध हों और घटना की रीति, जैसा कि वर्णित किया गया है, के लिए स्वतंत्रता साक्षी द्वारा भी पुष्टि किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, अंततः, यह सब मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह मृतक के करीबी लोग ही होंगे, जो वास्तविक अपराधियों को दंडित करने के लिए सबसे अधिक उत्सुक होंगे।"

उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, उच्च न्यायालय ने उन अभियुक्तों की दोषसिद्धि के निर्णय को, जिन्हें त्वरित निपटान न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया था और साथ ही उन पर अधिरोपित दंडादेश को निरस्त कर दिया और तदनुसार, सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त करके अपीलों को स्वीकार कर लिया।

20. आगे कार्यवाही करने से पूर्व, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील का विनिश्चय करते समय अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण का पुनर्विलोकन करना उपयोगी होगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 दो-मुक्ति के मामले में

अपीलों से संबंधित है।शीओ में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति को दोषमुक्त करने के आदेश के खिलाफ अपील पर कार्रवाई करने में उच्च न्यायालय की शक्तियों पर शुरुआती मामलों में से एक शिव स्वरूप बनाम आर. एम्परर, ए. आई. आर. 1934 पी. सी. 227 (2) में प्रिवी कांउसिल की न्यायिक समिति को दोषमुक्त करने के आदेश के खिलाफ अपील तक कार्यवाई करने में उच्च न्यायालय की शक्तियों पर शुरुआती मामलों में से एक की सुनवाई करते हुए अपील न्यायालय की शक्ति से संबंधित उपबंध और निम्नलिखित मत व्यक्त किया गयाः

> "16. तथापि, यह नहीं भूला जा सकता कि दोष-मुक्ति के मामले में अभियुक्त के पक्ष में दोहरी उपधारणा है। पहला, उसके लिए निर्दोषिता की उपधारणा आपराधिक न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांत के तहत उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाना चाहिए जब तक कि वह सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी साबित न हो जाए। दूसरा, अभियुक्त को बरी कर देने के बाद, उसकी निर्दोषिता की धारणा निश्चित रूप से कमजोर नहीं होती बल्कि निचली अदालत द्वारा मजबूत, पुष्ट और मजबूत होती है। किंतु संहिता द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए और तथ्य के आधार पर अपने निष्कर्षों पर पहुंचने से पहले उच्च न्यायालय को हमेशा ऐसे मामलों को उचित महत्व देना चाहिए और उन पर विचार करना चाहिए जैसे (1) विचारण न्यायाधीश के गवाहों की विश्वसनीयता के बारे में विचार करना, (2) अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषिता की उपधारणा, निश्चित रूप से इस तथ्य से कमजोर नहीं है कि उसे अपने विचारण में बरी कर दिया गया है, (3) किसी भी संदेह के लाभ के लिए अभियुक्त का अधिकार, और (4) किसी न्यायाधीश द्वारा किए गए तथ्यों के निष्कर्ष को परेशान करने में अपीलीय न्यायालय की धीमी गति, जिसे साक्षी को देखने का लाभ था।तथापि, इसका उल्लेख करने का अर्थ केवल यह है कि उच्च न्यायालय को अपील के अपने संचालन में न्याय प्रशासन में सुविख्यात और मान्यता प्राप्त नियमों और सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिए और करेगा।"

यह कहा गया कि अपीलीय न्यायालय के पास रिहाई की समीक्षा करने और उसे पलटने की पूरी शक्ति है।

21. एटली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 807, में निर्मुक्ति के निर्णय पर विचार करते समय अपील न्यायालय के दृष्टिकोण पर चर्चा की गई और यह मत व्यक्त किया गया कि जब तक अपील न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता कि निर्मुक्ति का निर्णय विकृत था, तब तक वह उसे अपास्त नहीं कर सकता। इसी तरह के प्रभाव के लिए इस न्यायालय ने न्यायमूर्ति सुब्बा राव के माध्यम से (तत्कालीन न्यायमूर्ति) सनवत सिंह बनाम राजस्थान राज्य, एआईआर 1961 एससी 715 में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की हैं:

> "9. उपर्युक्त चर्चा से निम्नलिखित परिणाम निकलते हैंः (1) अपीलीय न्यायालय को उस साक्ष्य का पुनर्विलोकन करने की पूरी शक्ति है जिस पर दोषमुक्ति का आदेश आधारित है। (2) स्वरूप का मामला इस तरह की अपील के निपटान के मामले में अपीलीय न्यायालय के दृष्टिकोण के लिए एक सही मार्गदर्शन प्रदान करता है और (3) इस न्यायालय के निर्णयों में उपयोग की गई विभिन्न शब्दावली, जैसे कि (i) 'पर्याप्त और बाध्यकारी कारण', (ii) 'अच्छे और पर्याप्त रूप से तर्कसंगत कारण', और (iii) 'मजबूत कारण' का आशय संपूर्ण साक्ष्य का पुनर्विलोकन करने के लिए दोषमुक्ति के खिलाफ अपील में अपीलीय न्यायालय की निश्चित शक्ति को कम करना और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचना नहीं है, बल्कि ऐसा करने में उसे न केवल तथ्य के प्रश्नों और कारणों के समर्थन में नीचे दिए गए अपने बरी करने के आदेश के समर्थन में प्रत्येक मामले पर विचार करना चाहिए।"

उपर्युक्त टिप्पणियों की आवश्यकता अहेर राजा खिमावास बनाम् सौराष्ट्र राज्य ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 217 के मामले में बहुमत की टिप्पणियों के कारण उत्पन्न हुई जिसमें यह कहा गया था कि उच्च न्यायालय को सबूतों पर अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त और बाध्यकारी कारण भी हैं कि विचारण न्यायालय गलत था।

22. एम. जी. अग्रवाल बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1963 एससी 200 इस न्यायालय की संविधान पीठ का निर्णय है, जो न्यायमूर्ति गजेन्द्रगडकर के माध्यम से बोल रहा है (जैसा कि उस समय था)। इस न्यायालय ने कहा कि बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर विचार करने में उच्च न्यायालय (अपीलीय न्यायालय) का दृष्टिकोण सतर्क होना चाहिए क्योंकि 16 में निर्दोषिता की धारणा "अभियुक्त के पक्ष में है निश्चित रूप से इस तथ्य से कमजोर नहीं होता कि वह अपने विचारण में बरी हो गया है।"

23. शिवाजी साहब राव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य वाले मामले में, (1973) 2 एस. सी. सी. 793 में न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने इस प्रकार मत व्यक्त कियाः

> “संक्षेप में, अनुमानित निर्दोषिता के लिए हमारे न्यायशास्त्र के उत्साह को आपराधिक न्याय को शक्तिशाली और यथार्थवादी बनाने की व्यावहारिक आवश्यकता द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। अपराधी को मुक्त करने के लिए पर्याप्त रूप से अवसर की संभावनाओं का पीछा करने और सीमांत निर्दोषों को दंडित करने के लिए प्रबल संभाव्यता के तर्क को काटने के बीच एक संतुलन बनाना होगा।"

24. इस न्यायालय ने रमेश बाबूलाल दोशी बनाम राजस्थान राज्य है। गुजरात, (1996) 9 एस. सी. सी. 225 वाले मामले में अभियुक्त को दोष-मुक्त करने के आदेश के विरुद्ध अपील पर विचार करते समय अपील न्यायालय के दृष्टिकोण के बारे में बात की और निम्नलिखित रूप में कहाः

> ‘बरी किए जाने के फैसले पर बैठते समय अपीलीय अदालत से पहले इस सवाल का जवाब मांगा जाता है कि क्या निचली अदालत के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से गलत, स्पष्ट रूप से गलत या टिकाऊ नहीं हैं। यदि अपील न्यायालय उपर्युक्त प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देता है तो दोषमुक्ति के आदेश में व्यवधान नहीं डालना है।इसके विपरीत, यदि अपीलीय न्यायालय, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, यह अभिनिर्धारित करता है कि उपरोक्त किसी भी कमियों को ध्यान में रखते हुए दोषमुक्ति के आदेश को

> किसी भी तरह से कायम नहीं रखा जा सकता है, तो वह फिर साक्ष्य का मूल्यांकन कर सकता है और फिर केवल अपने स्वयं के निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है।"

उपर्युक्त दृष्टिकोण का लक्ष्य और उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय की हत्या न हो। दूसरे शब्दों में, दोषी को बरी नहीं किया जाना चाहिए या किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।

25. अजीत सावंत मजगवई बनाम कर्नाटक राज्य (1997) 7 एस. सी. सी. 110 वाले मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए जो विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय द्वारा अपील की सुनवाई को विनियमित और शासित करेंगेः

> "16. इस न्यायालय ने इस प्रकार स्पष्ट और स्पष्ट रूप से उन सिद्धांतों को निर्धारित किया है जो विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा अपील की सुनवाई को नियंत्रित और विनियमित करेंगे। इन सिद्धांतों को अनगिनत मामलों में निर्धारित किया गया है और निम्नानुसार दोहराया जा सकता हैः
>
> (1) दोष-मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील में उच्च न्यायालय के पास सभी शक्तियां हैं और दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई करते समय उसके पास जो शक्तियां होती हैं उनसे कम नहीं हैं।
>
> (2) उच्च न्यायालय को पूरे मुद्दे पर पुनर्विचार करने, साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने और विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों के स्थान पर अपने स्वयं के निष्कर्ष और निष्कर्षों पर पहुंचने की शक्ति है, यदि उक्त निष्कर्ष अभिलेख पर साक्ष्य के महत्व के विरुद्ध है, या दूसरे शब्दों में विकृत है।

(3) दोषमुक्ति के निष्कर्ष को पलटने से पहले, उच्च न्यायालय को प्रत्येक आधार जिस पर दोषमुक्ति का आदेश आधारित था, पर विचार करना होगा और उन 18 को स्वीकार न करने के अपने कारणों को दर्ज करना होगा। आधार प्रदान करना और निचली अदालत द्वारा व्यक्त इस विचार का समर्थन न करना कि अभियुक्त बरी होने का हकदार है।

(4) दोषमुक्ति के निष्कर्ष को पलटते हुए, उच्च न्यायालय को इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि निर्दोषिता की उपधारणा अभी भी अभियुक्त के पक्ष में उपलब्ध है और वह विचारण न्यायालय द्वारा उसके पक्ष में पारित दोषमुक्ति के आदेश द्वारा मजबूत और मजबूत है।

(5) यदि उच्च न्यायालय का, साक्ष्य और अभिलेख पर अन्य सामग्री की नई संवीक्षा और पुनर्मूल्यांकन पर यह मत है कि एक और मत है जो युक्तियुक्त रूप से लिया जा सकता है, तो वह मत जो अभियुक्त के पक्ष में है, अपनाया जाना चाहिए।

(6) उच्च न्यायालय को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विचारण न्यायालय को गवाहों के आचरण को देखने और न्यायालय में उनके आचरण को देखने का लाभ प्राप्त है, विशेष रूप से साक्षी कठघरा में।

(7) उच्च न्यायालय को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उस स्तर पर भी अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का हकदार था।संदेह ऐसा होना चाहिए कि एक समझदार व्यक्ति अभियुक्त के अपराध के बारे में ईमानदारी और ईमानदारी से विचार करेगा।"

26. इस न्यायालय ने रमेश बाबूलाल दोशी बनाम राजस्थान राज्य बनाम् गुजरात, (1996) 9 एस. सी. सी. 225 वाले मामले में दोष-मुक्ति के निर्णय पर विचार करते समय अपीलीय न्यायालय की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित मत व्यक्त किया:

> "7. ...बरी किए जाने के फैसले पर बैठते समय अपीलीय अदालत को सबसे पहले इस सवाल का जवाब मांगने की आवश्यकता होती है कि क्या निचली अदालत के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से गलत हैं, स्पष्ट रूप से गलत हैं या टिकाऊ नहीं हैं।यदि अपील न्यायालय उपर्युक्त प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देता है तो दोषमुक्ति के आदेश में व्यवधान नहीं डालना है।इसके विपरीत, यदि अपीलीय न्यायालय, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, यह अभिनिर्धारित करता है कि उपरोक्त किसी भी कमियों को ध्यान में रखते हुए दोषमुक्ति के आदेश को बिल्कुल भी कायम नहीं रखा जा सकता है, तो वह फिर-और केवल-अपने निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है."

27. इस न्यायालय ने चंद्रप्पा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य कर्नाटक, (2007) 4 एस. सी. सी. 415 वाले मामले में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील की सुनवाई करते समय शक्ति का प्रयोग करने में एक महत्वपूर्ण अंतर है। अपीलीय न्यायालय उस स्थिति में हस्तक्षेप नहीं करेगा जहां आक्षेपित निर्णय साक्ष्य पर आधारित हो और लिया गया दृष्टिकोण तर्कसंगत और तर्कसंगत हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपीलीय न्यायालय इस तथ्य का अवधारण करेगा कि अभियुक्त के पक्ष में उपधारणा है और अभियुक्त संदेह का लाभ प्राप्त करने का हकदार है किंतु यदि वह हस्तक्षेप करने का विनिश्चय करता है तो उसे दो-मुक्ति के विनिश्चय से भिन्न होने के लिए कारण देने चाहिए।

28. निर्णयों के एक वर्ग के प्रति निर्देश करने के पश्चात्, इस न्यायालय ने दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील पर विचार करते समय अपील न्यायालय की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित सामान्य सिद्धांतों को चुना हैः

> "42. उपर्युक्त निर्णयों से, हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, 20 के संबंध में निम्नलिखित सामान्य सिद्धांत दो-मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील पर कार्यवाही करते समय अपील न्यायालय की शक्तियां उभर कर सामने आएंगीः

(1) अपीलीय न्यायालय को उस साक्ष्य का पुनर्विलोकन करने और पुनर्विलोकन करने की पूरी शक्ति है जिस पर दो-मुक्ति का आदेश आधारित है।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में ऐसी शक्तियों के प्रयोग पर कोई सीमा, निर्बन्धन या शर्त नहीं रखी गई है और अपीलीय न्यायालय तथ्य और विधि दोनों के प्रश्नों पर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व साक्ष्य पर कोई परिसीमा, निर्बन्धन या शर्त नहीं रखता है।

(3) विभिन्न अभिव्यक्तियां, जैसे कि "ठोस और बाध्यकारी कारण", "अच्छे और पर्याप्त आधार", "बहुत मजबूत परिस्थितियां", "विकृत निष्कर्ष" "स्पष्ट गलतियां", आदि का आशय दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में अपील न्यायालय की व्यापक शक्तियों को कम करना नहीं है। इस प्रकार की शब्दावली "भाषा के विकास" की प्रकृति की अधिक है, जो साक्ष्य की समीक्षा करने और अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए न्यायालय की शक्ति को कम करने के बजाय दोषमुक्ति में हस्तक्षेप करने के लिए अपीलीय न्यायालय की अनिच्छा पर जोर देती है।

(4) तथापि, अपीलीय न्यायालय को यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि दो-मुक्ति के मामले में अभियुक्त के पक्ष में दोहरी उपधारणा है। पहला, उसके लिए निर्दोषिता की उपधारणा आपराधिक न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांत के तहत उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि वह सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी साबित नहीं हो जाता है।दूसरा, अभियुक्त के बरी होने के बाद, उसकी निर्दोषिता की धारणा को निचली अदालत द्वारा और मजबूत किया जाता है।

(5) यदि अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर दो युक्तियुक्त निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के निष्कर्ष में बाधा नहीं डालनी चाहिए।"

29. नेपाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2009) 12 एस. सी. 351 में, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस निर्णय को उलट दिया जिसने विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए दोषमुक्ति के निर्णय को अपास्त कर दिया था और साक्ष्य के पुनः मूल्यांकन पर अभियुक्त को दोषमुक्त करने वाले विचारण न्यायालय के निर्णय को पुनःस्थापित कर दिया था।

30. उन परिस्थितियों को, जिनके अधीन इस न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील ग्रहण की जाएगी, संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता हैः

(अ) साधारणतया, यह न्यायालय दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप करने में सावधानी बरतता है, विशेष रूप से जब दोषमुक्ति के आदेश की उच्च न्यायालय तक पुष्टि की जा चुकी हो।यह केवल विरले मामलों में है, जहां उच्च न्यायालय ने तार्किकता की बिल्कुल गलत प्रक्रिया पर और मामले के तथ्यों के प्रति कानूनी रूप से गलत और विकृत दृष्टिकोण अपनाते हुए, कुछ सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी करते हुए, अभियुक्त को बरी कर दिया है, कि इस न्यायालय द्वारा संविधान की अनुच्छेद 136 के तहत अधिकारिता का उपयोग करते हुए इसे उलट दिया जाए। [उत्तर प्रदेश राज्य v।सहाय, एआईआर 1981 एससी 1442)

अपील ग्रहण करने के अधिकार पर ऐसी बेड़ियों को किसी ऐसे व्यक्ति का पर्दाफाश करने की अनिच्छा के कारण प्रेरित किया जाता है, जिसे किसी आपराधिक आरोप से सक्षम न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया है, भले ही यह एक वरिष्ठ न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया हो, मामले की आगे की जांच के लिए चिंता और तनाव है। [अरुणाचलम बनाम साधन नाथन, एआईआर 1979 (एससी) 1284]

किसी भी दोषमुक्ति के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार नहीं किया जा सकता, जो वैध और महत्वपूर्ण कारणों को दर्ज करने के बाद एक अजेय, तार्किक निष्कर्ष पर पहुंच गया है, जो दोषमुक्ति को न्यायोचित ठहराता है। [हरियाणा राज्य बनाम लखबीर सिंह, (1990) सीआरएलजे 2274 (एससी)]

(ब) तथापि, इस न्यायालय ने कुछ अवसरों पर, किसी उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त कर दिया।वे परिस्थितियां जिनके अधीन यह न्यायालय दो-मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील ग्रहण कर सकता है और दो-सिद्धि का आदेश पारित कर सकता है, निम्नलिखित रूप में संक्षेप किया जा सकता हैः

i) जहां उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण या तर्क विकृत हैः

(क) जहां अविवाद्य साक्ष्य को उच्च न्यायालय द्वारा संदेह और अनुमानों के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है, जो अवास्तविक है। [राजस्थान राज्य बनाम सुखपाल सिंह, एआईआर 1984 एससी 207] उदाहरण के लिए, जहां प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के प्रत्यक्ष, सर्वसम्मत खातों को बिना किसी छूट के छूट दी गई थी। तर्कसंगत आधार [उत्तर प्रदेश राज्य बनाम शंकर, एआईआर 1981 एससी 879]

(ख) जहां पीड़ित के घर में रहने वाले रिश्तेदारों की गवाही के आंतरिक गुणों को इस आधार पर छूट दी गई थी कि वे "रूचि रखने वाले" साक्षी बनते हैं [उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हकीम सिंह, ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 184]

(ग) जहां उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को फंसाने के लिए गवाहों के व्यक्तिगत उद्देश्य के अवास्तविक अनुमान पर गवाहों की गवाही को अस्वीकार कर दिया था, जबकि वास्तव में गवाहों के पास कथित गवाहों को दबाने के लिए कोई कुल्हाड़ी नहीं थी। [राजस्थान राज्य बनाम सुखपाल सिंह, एआईआर 1984 एससी 207]

(घ) जहां मृतक पीड़ित के मृत्युपूर्व कथन को उच्च न्यायालय द्वारा इस असंगत आधार पर नामंजूर कर दिया गया था कि उन्होंने 24 की जगह पर उपस्थित व्यक्तियों में से किसी एक पर लगी चोट की व्याख्या नहीं की थी। (अरुणाचलम ब. ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1284]

(ङ) जहां उच्च न्यायालय ने 'युक्तियुक्त संदेह से परे सबूत' के बजाय 'अंतर्निहित सबूत' के अवास्तविक मानक को लागू किया और इसलिए त्रुटिपूर्ण तरीके से साक्ष्य का मूल्यांकन किया। [उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रंझा राम, एआईआर 1986 एससी 1959]

(च) जहां उच्च न्यायालय ने एक अतिरंजित और स्वेच्छापूर्ण सिद्धांत के आधार पर पारिस्थितिक साक्ष्य को नामंजूर कर दिया, जो [महाराष्ट्र राज्य बनाम चंपल पंजाजी शाह, एआईआर 1981 एससी 1675] या जहां दोष-मुक्ति केवल आरोपी पक्ष में संदेह के लाभ के नियम के प्रति अतिशयोक्तिपूर्ण भक्ति में निहित है। [गुरबचन बनाम सतपाल सिंह, एआईआर 1990 एससी 209]।

(छ) जहां उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया कि उसका अपराध करने का कोई पर्याप्त आशय नहीं था, यद्यपि उक्त मामले में अभियुक्त का दोष सिद्ध करने के लिए ठोस प्रत्यक्ष साक्ष्य था, जिससे अभियोजन पक्ष की ओर से उद्देश्य को स्थापित करने के लिए अनावश्यक हो गया। [आंध्र प्रदेश राज्य बनाम बोगम चंद्रैया, एआईआर 1986 एससी 1899]

ii) जहां दोषमुक्ति का परिणाम न्याय की घोर हत्या होगीः

(क) जहां उच्च न्यायालय के निष्कर्ष, अभियुक्त व्यक्तियों को अपराध से अलग करने वाले थे, साक्ष्य के एक आकस्मिक विचार पर आधारित थे। [राज्य बनाम फेरू सिंह, ए. आई. आर. 1989 एससी 1205] या उन परिस्थितियों पर आधारित जो विशुद्ध रूप से कल्पना और मौज पर आधारित थीं [उत्तर राज्य प्रदेश बनाम पुस्सू 1983 एआईआर 867 (एससी)]

(ख) जहां अभियुक्त को विचारण के संचालन में विलंब के आधार पर दोषमुक्त कर दिया गया था, जो विलंब अभियोजन अभिकरणों की सुस्ती या उदासीनता के कारण नहीं था, बल्कि अभियुक्त के स्वयं के आचरण के कारण था या जहां विलंब के आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया था। किसी अपराध से संबंधित विचारण करने में, जो कोई तुच्छ प्रकृति का नहीं। [महाराष्ट्र राज्य बनाम चंपल पंजाजी शाह, एआईआर 1981 एससी 1675]

[स्रोतः डॉ.दुर्गा दास बसु-'द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1973' छठा संस्करण खंड II अध्याय XXIX]

31. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए हम अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करेंगे।

32. पी. डब्ल्यू. की संख्या 1,3,4 और 7 एक-दूसरे से संबंधित हैं और वे क्रमशः मृत छोटे लाल महतो के पुत्र और चचेरे भाई हैं। पी डब्लू ने अपनी जांच में कहा है कि 10.03.2005 को लगभग 05.00 बजे शाम को, उसने मुन्ना राम, महेंद्र राम, उपेंद्र राम, डप्पु राम और अन्य व्यक्तियों को अपनी दुकान के पास आते हुए देखा और छोटे लाल महतो (मृतक) और उसपुत्र राजेश प्रसाद अपीलकर्ता को गालियां देने लगे.उस मुन्ना राम ने छोटे लाल महतो पर बम फेंका और परिणामस्वरूप उसकी मौत हो गई। एम. ओ. पी. वर्मा की भी महेन्द्र राम के बम फेंकने से मृत्यु हो गई।तीसरा बम सड़क पर फेंका गया और इसने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। उसी समय, 20 से 25 लोगों ने अशोक यादव नाम के एक व्यक्ति को पकड लिया और उसे पीटना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप यह सुना गया कि उसकी मौत हो गई है।तथापि, अपनी प्रति-परीक्षा में, पी डब्लू-1 ने कहा है कि अभियुक्त और अन्य व्यक्ति एक दूसरे को गाली दे रहे थे.उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि पुलिस ने राजेश प्रसाद (पीडब्ल्यू-7) के समक्ष मामला दर्ज किया है या नहीं। उन्होंने कहा कि घटना से पहले जो कुछ भी हुआ था, उसके बारे में उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की है। उसने यह भी कहा है कि मृतक छोटे लाल महतो उसके ससुर हैं। उन्होंने कहा कि बम के विस्फोट के कारण क्षेत्र धुएं से भर गया था और पान की दुकान दिखाई नहीं दे रही थी। उसने पुलिस को दिए अपने बयान में यह भी स्वीकार किया है कि उसने कहा था कि महेंद्र राम, उपेंद्र राम और धप्पू राम उसकी दुकान पर आए और उसने अपने पिता को गाली देनी शुरू कर दी। छोटे लाल महतो ने ऐसा न करने और अवैध शराब न बेचने का अनुरोध किया। गाली-गलौज करने के बाद वे चले गए और दस मिनट बाद वापस आ गए। हालांकि, उसने स्वीकार किया है कि उसे याद नहीं है कि क्या उसने पुलिस के सामने कहा था कि उपेंद्र राम ने चिल्लाना शुरू कर दिया था और महेंद्र राम को मृतक को पकड़ने का निर्देश दिया था और उसके बाद महेंद्र राम ने एक बम फेंका था। उन्होंने आगे कहा है कि यह कहना गलत है कि अशोक यादव और अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बम फेंकने के कारण उनके पिता और अन्य व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।

33. पी डब्लू 2/ प्रभात कुमार सिंह ने कहा है कि वह एक पीसीओ (पब्लिक कॉल ऑफिस) बूथ चलाता है और 10.03.2005 को लगभग 5.00 बजे शाम को वह बूथ पर था।

राजेश प्रसाद (पीडब्लू-7) और महेंद्र राम, उपेंद्र राम और धप्पू राम के बीच झगड़ा हुआ था। उस मुन्ना राम ने छोटे लाल महतो की पान की दुकान पर एक बम फेंका, जिससे उसके सिर पर चोट लगी और उसका सिर फट गया। वह पीडब्लू गनीज 2 बम के टुकड़ों के संपर्क में भी आया और उसी के परिणामस्वरूप घायल हो गया.वह छोटे लाल महतो के शव को देखकर चकित हो गया और अपनी दुकान बंद करने के बाद वहां से चला गया। हालांकि, प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने कहा है कि वह विस्फोट के तीस मिनट बाद घटनास्थल से चला गया था।

34. उसने यह भी स्वीकार किया है कि वह पुलिस सुरक्षा में है क्योंकि उसे आरोपी द्वारा धमकी दी गई है कि यदि वह उनके खिलाफ गवाही देता है, तो उसे परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही कारण है कि वह पिछली शाम पुलिस थाने गया और पुलिस सुरक्षा में पेश हुआ। उन्होंने कहा है कि वह उदय प्रकाश मंडल को नहीं पहचानते जो अदालत में मौजूद थे। पी डब्लू 2 ने कहा है कि वह राजेश, मुखबिर के घर में किरायेदार है और उसने उस हलफनामे पर हस्ताक्षर किए जो उसके बयान के आधार पर तैयार किया गया था। उनके वकील ने सलाह दी थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने राजेश, नरेश या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को अशोक यादव को पीटते नहीं देखा था। यह कि लोगों के बीच विवाद खत्म होने के बाद वे घटना स्थल से चले गए। उन्होंने बताया कि घटना के बाद मुन्ना राम के एक सहयोगी ने उन्हें पकड़ लिया था। चंद्रभानु प्रसाद के परिवार ने मुन्ना राम को मौके से भागने में मदद की।

35. पी डब्लू 3/ नरेश प्रसाद @नरेश महतो ने कहा है कि 10.03.2005 को, उन्होंने मुन्ना राय (मुन्ना राम के रूप में पढ़ा जाना) को अपनी पान की दुकान के सामने अज्ञात व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए देखा, जिसमें कहा गया था कि वह अपने व्यवसाय में हस्तक्षेप करने वाले किसी भी व्यक्ति को नष्ट कर देगा। उसका भाई राजेश प्रसाद (पीडब्लू नंबर 7) उसके घर से बाहर आया और मुन्ना राय को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसने धमकी दी कि वह उसके पूरे परिवार को बम से उड़ा देगा। इस तरह की धमकी के बाद, वह महेंद्र राय, उपेंद्र राय (उपेंद्र राम के रूप में पढ़ने के लिए) और हप्पू राय (धप्पू राम के रूप में पढ़ने के लिए) के साथ दस मिनट के बाद ही वापस आ गए। उस मुन्ना राय ने उस पान की दुकान पर एक बम फेंका, जिसमें उसके पिता बैठे थे, जिससे उसके पिता का सिर उड़ गया

और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।एक अन्य बम मुन्ना राय द्वारा विस्फोट किया गया था और ओ. पी. वर्मा नामक एक पैदल यात्री की मृत्यु हो गई थी। वह अपने पिता के पास गया और रोने लगा। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं है।उसे यह भी पता नहीं है कि जब्ती सूची पर किसने हस्ताक्षर किए थे जिस पर उसके हस्ताक्षर पाए गए थे। जबकि उन्होंने आरोपी मुन्ना राय, महेंद्र राय, उपेंद्र राय, धप्पू राय, भानु जी (चंद्रभानु प्रसाद) की पहचान की, लेकिन उन्होंने एक अन्य व्यक्ति को नहीं पहचाना, जो आरोपियों में से एक था। उन्होंने पहले ही कहा था कि उन्होंने चंद्रभानु प्रसाद को घटना स्थल पर नहीं देखा था।

36. अपनी प्रतिपरीक्षा में, उसने कहा है कि अभियुक्त और उसके परिवार के सदस्यों के साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है।वास्तव में, उनके परिवारों के बीच न्योता पहनी (निमंत्रण का आदान-प्रदान) हुआ था। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि उनके और अशोक यादव और मुन्ना राय जैसे अन्य लोगों के बीच कोई झगड़ा था। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि घटना के दिन धप्पू की चाय की दुकान लूट ली गई थी। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि पुलिस पांच मिनट के भीतर घटना स्थल पर पहुंच गई थी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर, कोतवाली थाना ने उस समय अपना फ़र्दबयान रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन उसने राजेश, उमेश, अन्य ग्रामीणों और पीडब्ल्यू-3 का बयान लिया। यह कि दारोगा ने उनकी उपस्थिति में फारदबयान नहीं लिखा, बल्कि सादे कागजात पर उनके हस्ताक्षर लिए सादा कागज और वह नहीं जानता कि उस पर आवेदन में क्या लिखा गया था। उसने यह भी कहा है कि उसे अपने भाई द्वारा दी गई एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन में क्या लिखा गया था, उसके बारे में पता नहीं है क्योंकि जब ऐसा आवेदन किया गया था तो वह सो रहा था। पुलिस को दिए अपने बयान में उसने कहा है कि मुन्ना राय और अज्ञात व्यक्ति उसकी पान की दुकान पर आए और गालियां देने लगे।उसे याद नहीं है कि क्या उसने पुलिस को बताया था कि आरोपियों ने बम विस्फोट किया था।

37. उमेश प्रसाद राय पी डब्लू 4 हैं जिन्होंने महेंद्र राय, उपेंद्र राय, मुन्ना राय, धप्पू राय के दुर्व्यवहार के बारे में इस प्रभाव से बात की है कि जो कोई भी उनके अवैध कार्य में हस्तक्षेप करेगा या उसमें बाधा डालेगा उसे बम से उड़ा दिया जाएगा। इसके बाद मुन्ना राय ने एक बम पान की दुकान पर फेंका, जिसमें छोटा लाल महतो बैठा था और जिसके

परिणामस्वरूप उसका सिर फट गया। इसके बाद महेंद्र राय ने दूसरा बम फेंका, जो एक राहगीर ओ. पी. वर्मा को लग गया, जो मैसर्स आदित्य इलेक्ट्रॉनिक्स के पास खड़ा था और तीसरा बम उपेंद्र राय द्वारा विस्फोट किया गया, जो सड़क पर गिर गया और फट गया। इसके बाद वह छोटे लाल महतो के शव के पास गया और रोता रहा। बम की आवाज सुनकर कई लोग घटना स्थल पर जमा हो गए। कि छोटे लाल महतो की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट उनके सामने रखी गई थी और उन्होंने उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे।

38. अपनी प्रतिपरीक्षा में, उसने कहा है कि छोटे लाल महतो उसके चाचा थे। उसने कहा है कि घटना से पहले गाली दी गई थी, लेकिन उसे आरोपी और उसके भाइयों राजेश और नरेश (मृतक के बेटे) के बीच पहले से किसी हाथापाई के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यह कि उन्होंने घटना को देखने के बाद पास के पुलिस स्टेशन को सूचित नहीं किया था, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यह जानकारी दस मिनट के बाद पहुंचे पुलिस अधिकारियों को भेज दी गई।पुलिस ने घटना के दिन उसका बयान दर्ज नहीं किया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उनका फ़र्दबयान उनकी लिखावट में नहीं था और फ़र्दबयान पर हस्ताक्षर करने से पहले उन्होंने उसे नहीं पढ़ा था। उन्होंने कहा है कि राजेश और अशोक के बीच अवैध शराब को लेकर कोई विवाद नहीं था और यह सच नहीं है कि इस तरह के विवाद के दौरान एक हाथापाई हुई और अज्ञात व्यक्तियों ने बम विस्फोट किया जिसमें उनके चाचा और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। उन्होंने कहा है कि नरेश और राजेश के घर या उनके घर पर कोई बम नहीं फेंका गया था।कि घटना के दो महीने और बीस दिन बाद, वह अपना बयान दर्ज कराने गया क्योंकि कोई भी अधिकारी उसका बयान दर्ज करने नहीं आया कि, जब पहला बम फटा था, उस समय भगदड़ मची थी और उसे याद नहीं है कि अंधेरा होने के कारण दुकानदार अपनी दुकानें बंद करने लगे थे या नहीं। उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि एसपी ने राजेश के घर से अवैध शराब बरामद करने के निर्देश दिए थे, आदि।

39. पी डब्लू 7/राजेश प्रसाद सूचक है जो मृतक छोटे लाल महतो और इसमें अपीलार्थी का पुत्र है। अपनी परीक्षा बेल्जियम चीफ में, उसने कहा है कि 10.03.2005 को लगभग 05.00 बजे वह अपने घर के दरवाजे पर था और उसने महेंद्र राय, उपेंद्र राय और मुन्ना राय और अन्य अज्ञात व्यक्तियों को अपने घर के पास आते हुए देखा और धमकी दी कि

वे उसके पूरे परिवार को बम से उड़ा देंगे। मुन्ना राय ने तुरंत अपने पिता छोटे लाल महतो पर बम फेंक दिया, जो अपनी पान की दुकान में बैठे थे और उनके पिता के सिर का पिछला हिस्सा उड़ गया, जिससे उनकी तुरंत मौत हो गई। इसके बाद महेंद्र राय ने मैसर्स अदिति इलेक्ट्रॉनिक्स के पास एक और बम फेंका, जिसने एक राहगीर ओ. पी. वर्मा को मारा, जिससे उसका सिर फट गया और उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई। फिर उपेंद्र राय ने बम फेंका जो सड़क पर गिरा और फट गया। आरोपियों ने उन्हें एक बार फिर धमकी दी और मौके से फरार हो गए।इस घटना के पीछे कारण यह है कि आरोपी शराब का अवैध कारोबार कर रहे थे और उन्होंने और उनके परिवार के सदस्यों ने इसका विरोध किया और इसलिए, एक साजिश और एक आम इरादा था जिसके तहत उनके पिता की हत्या कर दी गई।कि उसने पुलिस स्टेशन (प्रदर्शनी संख्या 2/2) में अपने हस्ताक्षर के तहत एक लिखित शिकायत दर्ज की। उनके पिता के शव की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट उनकी उपस्थिति में तैयार की गई थी और उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए थे (प्रदर्शनी संख्या 4/1)।उन्होंने अदालत में मौजूद छह आरोपियों की भी पहचान की।

40. अपनी प्रतिपरीक्षा में, उसने कहा है कि उसने चंद्रभानु प्रसाद को घटना के स्थान पर नहीं देखा था। उन्होंने घटना की शुरुआत से अंत तक धप्पू राय को नहीं देखा। उन्होंने जो लिखित शिकायत तैयार की थी, उसे पढ़ा गया और उसमें से कुछ को सुना गया। उन्होंने इसे पूरी तरह से नहीं पढ़ा। शाम 6 बजे थाने में शिकायत दर्ज कराई गई कि उसने अपना मामला पेश करने के लिए एक निजी वकील की सेवाएं ली हैं। उन्हें पहली सूचना रिपोर्ट नहीं पढ़कर सुनाई गई।कि वह पूरी तरह से नहीं जानता कि पहली सूचना रिपोर्ट में क्या लिखा गया है। उन्हें यह भी नहीं पता कि उन्होंने विरोध याचिका में क्या उल्लेख किया था कि उनके वकील ने उन्हें इस तरह से लिखी गई पहली सूचना रिपोर्ट दी थी और उन्होंने अभी-अभी विरोध याचिका पर हस्ताक्षर किए थे और उन्होंने इसे पढ़ा नहीं था। और इसे समझ लिया कि उसके किसी भाई या रिश्तेदार ने कभी केस डायरी, पर्यवेक्षण नोट और विरोध याचिका नहीं पढ़ी है।

41. उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि महेंद्र, उपेंद्र, मुन्ना और उनके परिवार के बीच कोई विवाद या मुकदमेबाजी नहीं थी।उस कथित घटना की तारीख पर, उसके पिता और मुन्ना के बीच कुछ तीखी बहस हुई, लेकिन वह नहीं जानता कि उसने उक्त तथ्य को पहली सूचना

रिपोर्ट में या अपनी विरोध याचिका में या पुलिस के समक्ष बताया है। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि घटना से पहले उनके बीच कोई विवाद था।उन्हें यह भी नहीं पता कि घटना के तुरंत बाद पुलिस को सूचित किया गया था या नहीं।कि पुलिस अपराध स्थल पर लगभग 05.00 और 05.30 बजे आई, लेकिन वह नहीं जानता कि कौन सा विशेष पुलिस अधिकारी वहां आया था।उन्हें इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है कि निरीक्षक ने फरदबयान दर्ज किया या उपेंद्र, उनके भाई या उनके परिवार के सदस्यों के बयान उसी दिन पुलिस द्वारा दर्ज किए गए थे या नहीं, लेकिन उनका बयान दर्ज किया गया था।

42. इसके अलावा, अपनी प्रतिपरीक्षा में, पी डब्लू ने आगे इस बात से इनकार किया है कि उसने निरीक्षक, पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपाधीक्षक के समक्ष लगभग 04.00 से 04.30 तक की घटना से पहले कोई बयान दिया था। बाद में, अभियुक्तों ने ग्रामीणों को बिना संसदीय भाषा में गाली दी और जब वे इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो वे घर से बाहर आ गए और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। आरोपी धमकी देकर वहां से फरार हो गए। उन्होंने इस आशय का कोई बयान देने से भी इनकार किया कि उपेंद्र राय ने बम विस्फोट किया जो सड़क पर गिरने के बाद फट गया। उन्होंने निरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक के समक्ष दिए गए अपने बयान की पुष्टि की है कि मैसर्स अदिति इलेक्ट्रॉनिक्स के पास महेंद्र राय द्वारा एक बम विस्फोट किया गया था, जिसने एक राहगीर ओ. पी. वर्मा को मारा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि उन्हें याद नहीं है कि क्या उन्हें पुलिस के पास अपने फरदबयान में दर्ज कराया गया था कि भागते समय, एक आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया था और लगभग पीट-पीट कर मार दिया गया था।उन्होंने आगे कहा है कि उन्हें मामले के किसी अन्य पहलू की याद नहीं है। इसके बेहतर मूल्यांकन के लिए, उनके अभिसाक्ष्य के पैराग्राफ 21 को इस प्रकार उद्धृत करना उपयोगी होगाः

> "21. मुझे याद नहीं है कि क्या मैंने पुलिस के साथ अपने फ़र्द बेयान में दर्ज किया था कि भागते समय, एक आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया था और उसे पीटने के बाद लगभग मार डाला था। मुझे याद नहीं है कि मैंने पुलिस को यह बयान दिया था कि मैंने अपना मोजा खींच लिया और मुन्ना राय को पकड़ लिया, जिसे चंद्रभान और मुन्ना राय के भाई ने मुक्त कर दिया था और

वह भाग गया था। मुझे याद नहीं कि मैंने कहा था कि तब चंद्रभान और टप्पू ने कहा था कि हमारा काम अब पूरा हो गया और वे वहां से भाग गए।ऐसा नहीं है कि महेंद्र, उपेंद्र और मुन्ना ने अपराध नहीं किया है। और इसलिए, मैं हर बार कह रहा हूं कि मुझे पता नहीं है।

इसके अलावा, पैरा संख्या २५ और २६ में, पी डब्लू ७ सूचक (अपीलार्थी) ने निम्नानुसार कहा हैः

"25. ऐसा नहीं है कि मेरा भाई, भाई इंलेसाइस इन इंलेसाइस, उमेश और मैंने मिलकर जंक्शन मोड़ के पास अज्ञात अपराधियों को बुरी तरह पीटा और वे नाराज हो गए और उनमें से एक ने कहा कि यहां रुको हम कुछ मिनटों में वापस आ रहे हैं और फिर उन्होंने बम विस्फोट कर दिया। ऐसा नहीं है कि कुछ ही मिनटों के बाद अपराधी बम लेकर आए और मुझे मारने के लिए गाली दे रहे थे, मेरे भाई, उमेश और भाई मीलमेनी को मार रहे थे और फिर हम अपनी जान बचाने के लिए अपने घर की ओर भागे और फिर बम फेंक दिया, जो अदिति इलेक्ट्रॉनिक्स के पास गिरा और हम वहां से भागने में सफल हो गए और घर के अंदर खुद को बंद कर लिया और जब वे हमें नहीं पा रहे थे, तो अज्ञात अपराधियों ने हमारी दुकान में हमारे पिता पर बम विस्फोट कर दिया। ऐसा नहीं है कि जब बम फटने के बाद आरोपी व्यक्ति भागने लगे, तो ग्राम के लोगों ने शोर मचाया और फिर सभी लोग इकट्ठा हो गए और एक अपराधी को पकड़ने में कामयाब हो गए और उसे पीट-पीट कर मार डाला। ऐसा नहीं है कि जब हमने गांव वालों की आवाज सुनी कि पिलीज पिलीज पिलीज पिलीज पिलीज पिलीज, पिलीज पिलीज पिलीज पिलीज, हम दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले और हमने मिलकर अज्ञात अपराधी को पीटा।ऐसा नहीं है कि हमने ग्राम के लोगों के सामने तेज आवाज में नहीं कहा कि वो तप्पु राय और मुन्ना राय की दुकान पर काम करता है, लूटता है और फिर हमने तप्पू राय और मुन्ना राय की दुकान लूट ली और उसे नष्ट कर दिया। टप्पू राय की कोई दुकान नहीं है।

26. सीजेएम की अदालत के सामने टप्पु राय की चाय की दुकान है, जो अब नष्ट हो गई है।ऐसा नहीं है कि जब हमने लोगों को टप्पू राय और मुन्ना राय की दुकान को लूटने और नुकसान पहुंचाने के लिए कहा, तो उनके परिवार के महेंद्र और उपेंद्र और उनके परिवार के अन्य सदस्य आए और उन्होंने हमारे इस इरादे का विरोध किया और फिर हमने साजिश रची। उन्होंने एक नया आवेदन तैयार किया और उन्हें फंसाने के लिए रात में 9 बजे पुलिस स्टेशन में जमा किया।"

अपनी आगे की प्रतिपरीक्षा में, पैरा 29, पीडब्लू विलेन 7 में उन्होंने निम्नलिखित रूप में कहा हैः

"29.....इससे केवल ओ. पी. वर्मा को ही चोट पहुंची। मैंने पुलिस और पुलिस उप-आयुक्त के समक्ष ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि कुल मिलाकर पांच बम विस्फोट हुए।ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि कुल मिलाकर पांच बम विस्फोट हुए।"

पुलिस उपाधीक्षक के समक्ष उसके बयानों के संबंध में, पीडब्लू-7 ने स्पष्ट रूप से कहा हैः

"31. पुलिस उपाधीक्षक साहब के सामने मेरा बयान दर्ज नहीं किया गया। एक बार फिर कहा कि मुझे नहीं पता कि मैंने यह बयान डीएसपी साहब के सामने दिया है या नहीं।मैं नहीं जानता कि विरोध याचिका में मैं एसपी से अनुरोध करता हूं कि जांच किसी सुपीरियर ऑफिसर को सौंप दें।एसपी पर्यवेक्षण के लिए गए थे या नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता।

32. ऐसा नहीं है कि डीआईजी के आदेश पर एसपी ने व्यक्तिगत रूप से अपराध स्थल का निरीक्षण किया था।मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। ऐसा नहीं है कि घटना की सच्चाई को छिपाने के लिए, मैं कह रहा हूं कि मैं अनपढ़ हूं और एसपी साहब द्वारा किए गए निरीक्षण के बारे में तथ्य छिपा रहा हूं।

33. ऐसा नहीं है कि मैंने एसपी को बयान दिया कि नरेश, बबलू, आतिश और मैंने अशोक यादव को बहुत बुरी तरह से पीटा और जब मुन्ना उसके बचाव के लिए आया, तो हमने उसे भी पीटा और फिर वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गया।(आपत्ति)।"

बम फेंके जाने के पहलू के संबंध में, पीडब्ल्यू-7 ने पैराग्राफ 35 और 36 में निम्नलिखित रूप में कहा हैः

"35. यह कहना गलत है कि जब पहला बम विस्फोट हुआ, तो ट्रैफिक में भगदड़ मच गई और लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए खुद को छिपाना शुरू कर दिया और दुकान बंद होने लगी और हम अपना जीवन बचाने के बाद वहां से भाग गए। यह कहना गलत है कि उसके बाद अशोक यादव ने मेरी पान की दुकान पर बम फेंका, मेरे पिता की मृत्यु हो गई और उसके बाद ग्राम के लोगों ने अशोक यादव को पकड़ लिया और उसकी मृत्यु होने तक उसकी पिटाई की।

36. यह कहना गलत है कि शेष राशि की मांग को लेकर अशोक यादव के साथ झगड़ा हुआ था और उसे पीटा गया था और उपरोक्त कारण से उसने बम विस्फोट किया था।"

43. पीडब्ल्यू 9/मणि लाल सहवास 10 मार्च, 2005 को मुंगेर के थाना कोतवाली में तैनात सब इंस्पेक्टर थे। अजहर और के. के. गुप्ता के साथ एक सशस्त्र बल के साथ भदियोपुर गोला रोड के लिए रवाना हुए और 17.20 बजे वहां पहुंचे।वहां पहुंचने पर राजेश प्रसाद पुत्र स्वर्गीय छोटे लाल महतो ने संज्ञेय अपराध के बारे में एक लिखित आवेदन (प्रदर्शन 3/3) दिया। कथित आवेदन के आधार पर, उसने घटना के स्थान पर मामले की जांच शुरू की और जांच के दौरान, मुखबिर का बयान फिर से लिया गया और मामला दर्ज कर लिया गया। इसके बाद छोटे लाल महतो की जांच रिपोर्ट तैयार की गई (प्रदर्शन 4/2), साथ ही दिवंगत ओ. पी. वर्मा की जांच रिपोर्ट भी तैयार की गई। उनके शवों को एक कांस्टेबल के साथ पोस्टमॉर्टम के लिए 19.30 बजे सदर अस्पताल, मुंगेर भेजा गया।बम के अवशेष एकत्र किए गए और जब्ती

सूची तैयार की गई (प्रदर्शन 1/2), इसलिए खून से सने मिट्टी को भी एकत्र किया गया और जब्ती सूची प्रदर्शनी संख्या 8 में है कि छोटे लाल महतो का शव मृतक के रिश्तेदारों द्वारा पान की दुकान से बाहर लाया गया था। पान की दुकान के अंदर खून और मांस बिखरा हुआ था क्योंकि मृतक छोटे लाल महतो का सिर और गर्दन उड़ गई थी। दूसरा विस्फोट फुटपाथ पर मैसर्स आदित्य इलेक्ट्रॉनिक्स के पास मृतक की पान की दुकान के उत्तर की ओर लगभग 40 से 45 गज की दूरी पर हुआ। मृतक की पहचान चाय विक्रेता ओम प्रकाश वर्मा के रूप में हुई है।इसी तरह की बरामदगी घटना स्थल पर की गई।

44. उन्होंने आगे कहा कि संतोष कुमार पाटिल और अनिल महतो ने एक ही दिन अपने बयान दिए। आरोपी फरार थे। उसी दिन अन्य व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए और 12 मार्च, 2005 को प्रातः 06.40 बजे अभियुक्त मुन्ना राय और धप्पू राय को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 18 अप्रैल, 2005 को जांच एक अन्य अधिकारी को हस्तांतरित कर दी गई।

45. अपनी प्रतिपरीक्षा में, उक्त गवाह ने कहा है कि राजेश प्रसाद मुखबिर ने महेंद्र राय और उपेंद्र राय के बारे में बम विस्फोट के बारे में नहीं बताया था।घटना के स्थान पर दर्ज किए गए फरदबयान का उल्लेख करते हुए, पी डब्लू ने निम्नानुसार कहा हैःमुखबिर के बयान में यह दर्ज नहीं है कि महेंद्र राय, उपेंद्र राय, धप्पू राय मौजूद थे, इसके बजाय, उसने कहा है कि मुन्ना राय बम लाने के लिए घर गया था और उस समय उसका भाई भी वहां था।उमेश प्रसाद ने यह नहीं कहा कि जब मुन्ना राय, महेंद्र राय, उपेंद्र राय और धप्पू राय गाली दे रहे थे और कह रहे थे कि जो भी उनकी अवैध गतिविधि पर आपत्ति करेगा उसे उड़ा दिया जाएगा। उमेश प्रसाद ने अपने बयान में इस बात का उल्लेख नहीं किया कि दूसरा बम महेंद्र राय ने उड़ाया था, जो मैसर्स आदित्य इलेक्ट्रॉनिक्स के पास खड़े ओ. पी. वर्मा नाम के एक राहगीर से टकराया और उसका सिर उड़ गया। इसी तरह, ऐसा कोई बयान नहीं था कि तीसरा बम महेंद्र राय द्वारा विस्फोट किया गया था, जो सड़क पर गिरा और तेज आवाज हुई।

46. इसके अतिरिक्त, फरदबयान और अपने कथन में, अपीलार्थी राजेश प्रसाद ने यह नहीं कहा था कि मुन्ना राय, उपेन्द्र राय, महेन्द्र राय और धप्पू राय उसके पिता की पान की

दुकान के पास आए और गाली-गलौज शुरू कर दी और उसके पिता द्वारा प्रतिशोध लेने पर, वहां तीखी बहस हुई और उन्होंने उसे बम से उड़ा देने की धमकी दी।

47. पी. डब्ल्यू.8/ संतोष कुमार पटेल ने अपनी परीक्षा में कहा है कि 10.03.2005 को लगभग 05.00 बजे शाम को वह अपने गेट के पास खड़ा था और उसने आरोपी और छोटे लाल महतो को अशोभनीय और गलत गालियां देते हुए देखा और छोटे लाल महतो के परिवार को बम से उड़ाने की आरोपी की धमकी सुनी और आगे, कि छोटे लाल महतो के सिर को मुन्ना राय ने उड़ा दिया।लेकिन अपनी प्रतिपरीक्षा में, उसने कहा है कि वह अपने घर से 100 गज दूर घटना को नहीं देख सकता था। उन्होंने आगे कहा है कि उनका बयान पुलिस द्वारा घटना के स्थान पर और घटना के दिन रात 8 बजे दर्ज किया गया था। लेकिन उसने पुलिस को यह नहीं बताया था कि तीसरा बम सड़क पर फेंका गया था, जो किसी को नहीं लगा। इसके तुरंत बाद, क्षेत्र के लोग इकट्ठा हो गए और लोग आक्रामक हो गए और दोनों उपद्रवियों को पकड़ने की कोशिश की। उसने आगे स्वीकार किया है कि वह उन्होंने यह नहीं बताया कि बम राजेश की दुकान पर फेंका गया था जहां उसके पिता बैठे थे और बम ने उन्हें मारा था।

48. उपर्युक्त साक्ष्य पर विचार करने पर, हम पाते हैं कि पी डब्लू 7, जो अपने साक्ष्य में मुखबिर है, उसने पुलिस को जो शुरू में बताया था, उससे परेशान हो गया है, भले ही वह घटना का एक चश्मदीद गवाह होने का दावा करता है। यह स्थापित किया गया है कि चंद्र भानु प्रसाद हालांकि इलाके के निवासी थे, घटना के समय मौजूद नहीं थे। इसी तरह, धप्पू राम और फन्टुश मंडल की उपस्थिति पर पीडब्ल्यू-8 द्वारा संदेह किया जाता है। वास्तव में, जांच अधिकारी/पी डब्लू-9 ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है कि पी डब्लू ७ ने महेंद्र राम, उपेंद्र राम द्वारा फेंके जा रहे बमों के बारे में कुछ नहीं कहा था और यह कि धप्पू राम का कोई उल्लेख नहीं था. पी डब्लू ३ के बयान में, धप्पू राम, मुन्ना राम और महेंद्र राम का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और पी डब्लू २ के साक्ष्य में भी.इसके अलावा, पी डब्लू 4, जो एक अधिवक्ता है और जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने लिखित रिपोर्ट तैयार की है, उसके साक्ष्य में स्पष्ट नहीं किया गया है.पी डब्लू 8, जो एक अधिवक्ता और लिखित रिपोर्ट के लिए एक अनुप्रमाणक गवाह भी है, द्वारा इसका खंडन किया जाता है, कि बम मुखबिर की दुकान पर फेंका गया था

और यह कि इसने मुखबिर के पिता को मारा था जिसकी उसी के परिणामस्वरूप मृत्यु हो गई थी।

49. उपर्युक्त साक्ष्य के आधार पर उच्च न्यायालय ने अपने तर्क के दौरान निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले हैं:

(क) लिखित रिपोर्ट विशिष्ट है, लेकिन इसमें चंद्रभानु प्रसाद की एक छोटी सी भूमिका का उल्लेख किया गया है, जो धप्पू राम और अन्य के साथ थे। चंद्रभानु प्रसाद के आदेश पर तीन बम फेंके गए। चंद्रभानु प्रसाद ने सह-अपराधी मुन्ना राम को उस समय मुक्त कर दिया जब वह गिरफ्तार किया गया था।

ख) पीडब्ल्यू 7, सूचक, घटना का एक प्रत्यक्षदर्शी गवाह था। अपनी प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने कहा कि उन्होंने चंद्रभानु प्रसाद और धप्पू राम को कभी नहीं देखा था, जो एक ही इलाके के निवासी थे और उन्हें अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने फैंटस मंडल की पहचान करने से भी इनकार कर दिया, जिसका नाम जांच के दौरान सामने आया।

(ग) पी डब्लू-2 ने कहा कि चंद्रभानु प्रसाद इलाके का निवासी था और उसे पता था लेकिन पूरी घटना के दौरान वह मौजूद नहीं था.इसी प्रभाव के लिए पीडब्लू डायलिसिस 3 और पीडब्लू डायलिसिस 4 का बयान है.पीडब्ल्यू-8 ने भी कहा कि धप्पू राम और फैंटस मंडल मौजूद नहीं थे।

(घ) हालांकि, पीडब्लूएस 1,2,3 और 4 ने धप्पू राम की उपस्थिति के बारे में बात की और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत अपने बयानों में अपना नाम दिया।

(ङ) पी डब्लू-9, जांच अधिकारी ने कहा है कि सूचना देने वाले ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १६१ के तहत अपने बयान में महेंद्र राम और उपेंद्र राम द्वारा बम फेंके जाने के बारे में कुछ भी नहीं कहा था और न ही उसने धप्पू राम का नाम लिया था।

(च) कि विचारण के दौरान, पी डब्लू 3 ने धप्पू राम, मुन्ना राम और महेंद्र राम का नाम नहीं लिया था और पी डब्लू 2 ने इसी तरह मुन्ना राम, महेंद्र राम, उपेंद्र राम और धप्पू राम का नाम नहीं लिया था.अपने पुनर्कथन में भी उसने यह नहीं कहा कि मुन्ना राम,

महेंद्र राम, उपेंद्र राम और धप्पू राम उसके पिता की दुकान पर आए थे और गाली-गलौच में शामिल थे।

छ) इसी तरह, पी डब्लू 8 ने भी कोई बयान नहीं दिया था, जैसा कि अदालत में पेश किया जा रहा था।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:

> "अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान में विरोधाभास, जैसा कि जांच के दौरान कहा गया था और मुकदमे में साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 में दिए गए तरीके से उन्हें बताया गया था, और साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के तहत जांच अधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी, बचाव पक्ष के इस आरोप को विश्वसनीयता प्रदान करता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा पूरी तरह से एक नया मामला बनाने की कोशिश की गई थी, जो अनिवार्य रूप से एक अलग तरीका और घटनाओं का क्रम था।"

झ) पुलिस ने कहा कि वे घटना के 20 मिनट के भीतर अर्थात शाम 5.20 बजे घटनास्थल पर पहुंचे थे, जिसकी सूचना देने वाले और अन्य अभियोजन गवाहों, पीडब्ल्यू और पीडब्लू ने पुष्टि की है। पीडब्ल्यू-7 ने रात 9 बजे पुलिस स्टेशन को दी गई किसी भी लिखित रिपोर्ट से इनकार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पीडब्ल्यू द्वारा तैयार की गई लिखित रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उन्हें इसकी सामग्री के बारे में जानकारी नहीं थी।

ण) पी डब्ल्यू-7 के अनुसार पी डब्ल्यू 7, पी डब्ल्यू 4, जो एक अधिवक्ता हैं और पी डब्ल्यू 7 के चचेरे भाई हैं, ने एक लिखित रिपोर्ट तैयार की। पी डब्लू ७ ने स्वीकार किया कि वह एफ आई आर के लिए एक अनुप्रमाणक गवाह है लेकिन हस्ताक्षर करने से पहले उसे पूरी तरह से जानने या पढ़ने से इनकार किया।

(ट) पीडब्ल्यू-8, पीडब्ल्यू डायलिसिस 7 के एक रिश्तेदार द्वारा भी ऐसा ही खंडन किया गया है। पी डब्लू 8 एक अधिवक्ता और लिखित रिपोर्ट के लिए एक अनुप्रमाणक गवाह भी है.

50. उपर्युक्त साक्ष्य पर उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया:

> "वे गँवार गवाह नहीं थे, लेकिन वकालत कर रहे अधिवक्ता थे और जिन दस्तावेजों पर वे हस्ताक्षर कर रहे थे, उनकी प्रकृति और महत्व के बारे में पूरी तरह से अवगत थे।उनके इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि उन्होंने पूरी सामग्री से अनजान होकर हस्ताक्षर किए हैं।यह गंभीर संदेह पैदा करता है कि वे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे थे।"

51. लिखित रिपोर्ट के संबंध में, उच्च न्यायालय ने साक्ष्य से निम्नलिखित उल्लेख किया है:

> "इस विलम्ब के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, हालांकि लिखित रिपोर्ट पुलिस को सौंपे जाने के समय उन्हें थाना में मौजूद माना जा सकता है।"

52. उच्च न्यायालय ने मामले की जांच और अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में खामियों को भी नोट किया है, जो निम्नलिखित हैं:

(i) पी डब्लू-7 ने कहा कि पी डब्लू-4 ने लिखित रिपोर्ट तैयार की जबकि पी डब्लू-4 ने इसका खंडन किया।

(ii) जबकि पी डब्लू1 और पी डब्लू 3 मृतक से संबंधित थे और घटना के तुरंत बाद जब्ती सूची पर हस्ताक्षर किए थे, फिर भी पी डब्लू 3 ने कहा था कि वह जब्ती सूची के अन्य हस्ताक्षरकर्ता के बारे में अवगत नहीं था।

(iii) पी डब्ल्यू 1 का बयान, जो जब्ती सूची के गवाह के साथ-साथ एक चश्मदीद गवाह था, डेढ महीने बाद पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था, जिसका कोई स्पष्टीकरण गवाह या पुलिस की ओर से नहीं दिया गया।

(iv) इसी तरह, पी डब्लू 4 का बयान, जो एक चश्मदीद गवाह और मृतक की जांच रिपोर्ट का एक गवाह है और जिसके बारे में कहा गया है कि उसने पुलिस को दी गई लिखित रिपोर्ट तैयार की थी, पुलिस द्वारा दो महीने और बीस दिनों के बाद दर्ज किया गया था। उच्च न्यायालय ने नोट किया है कि विलंब के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है, हालांकि जब लिखित रिपोर्ट पुलिस को सौंपी गई तो उसे पुलिस स्टेशन में मौजूद होने की कल्पना की जा सकती है।

(v) घटना के दौरान मृतक की पान की दुकान के बगल में पीसीओ बूथ का दुकान मालिक पीडब्लू-2 भी कथित रूप से घायल हो गया था, लेकिन कोई चोट की रिपोर्ट नहीं है।

(vi) पी डब्लू 3 के साक्ष्य में विरोधाभास निम्नानुसार हैः

> "उस पी डब्लू ३ ने कहा है कि पुलिस २० से २५ मिनट के भीतर आई और मुखबिर, पी डब्लू ३ और अन्य का बयान लिया, लेकिन उसने कहा है कि पी डब्लू ७ ने पुलिस को रात ९ बजे लिखित रिपोर्ट दी, कि वह उस समय सो रहा था और इसके बारे में अनभिज्ञ था, फिर भी उसने कहा कि रिपोर्ट दूसरी ओर पी डब्लू ७ पर ८. ३० पर दी गई हो सकती है कि लिखित रिपोर्ट पुलिस को दी गई थी। दूसरी ओर, पी डब्लू 9, जो मामले में आईओ है, ने कहा कि पी डब्लू 7 ने घटना स्थल पर पहुंचने के तुरंत बाद उसे लिखित रिपोर्ट दी।"

(vii) जबकि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने तीन या अधिक बम फेंकने का आरोप लगाया, जांच अधिकारी ने कहा कि उन्हें केवल दो विस्फोटों के संकेत मिले-पहला मृतक की पान की दुकान पर और दूसरा मेसर्स आदित्य इलेक्ट्रॉनिक्स के पास, जो पहले विस्फोट की जगह से 40 गज उत्तर में स्थित है।

53. घटना की तारीख को हुए विस्फोटों के संबंध में, उच्च न्यायालय ने पी डब्लू 7, पी डब्लू 1 और पी डब्लू 9 के सबूतों पर विचार किया है और इस प्रकार कहा हैः

“पूर्वोक्त सामग्री और साक्ष्य की प्रकृति पर विचार करने पर यह न्यायालय संतुष्ट है कि अभियुक्त के खिलाफ आरोपों को सभी उचित संदेहों से परे साबित नहीं किया जा सकता है.गवाहों के बयान में कई विसंगतियां, विरोधाभास और अन्य आवश्यक सामग्री इस न्यायालय को संतुष्ट करती है कि उन्होंने घटना के बारे में प्रकट करने की मांग से अधिक छिपाने का प्रयास किया है.ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन द्वारा घटना का एक अलग तरीका और अनुक्रम उनकी सुविधा के लिए एक संक्षिप्त तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन लोगों को फंसाया गया है और उन लोगों को दोषमुक्त किया गया है जिनके खिलाफ मूल रूप से आरोप लगाए गए थे। पहले के आरोपियों को प्राथमिक भूमिका के साथ और जिनके संबंध में जिन्होंने पुलिस के सामने बयान नहीं दिया, उन्हें बरी करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। ये सभी कारक अभियोजन पक्ष के मामले पर गंभीर संदेह पैदा करते हैं।

अदालत में मुखबिर ने दो सह-अभियुक्तों को बरी किए जाने के बाद पूरी उत्पत्ति और घटना के तरीके को छोड़ दिया है। सूचक के गलत निहितार्थ को स्वीकार करने के बाद उस पर सच बोलने का भरोसा नहीं किया जा सकता। फाल्सस इंन यूनो फाल्सस इन ओम्नीबस के सिद्धांत का मामले के तथ्यों में कोई उपयोग नहीं है, जब अभियोजन ने स्वयं अपने मामले की आधारभूत इमारत को परिधीय मुद्दों से अलग कर दिया है।

अभियोजन पक्ष ने अपने गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्यों की प्रकृति के बावजूद, साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 के तहत उनकी फिर से जांच करना या उसी की धारा 154 के तहत उनकी प्रति परिक्षण करना आवश्यक नहीं समझा।

दोनों पक्षों के बीच मुकदमे के दौरान उजागर की गई अवैध शराब व्यापार प्रतिद्वंद्विता, इस न्यायालय को संतुष्ट करती है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, आरोप को सभी उचित संदेह से परे साबित नहीं किया जा

सकता है। इसके विपरीत, अभियोजन पक्ष ने अपने लिए एक मकड़जाल तैयार किया है और खुद को इसमें समेट लिया है, जिसका लाभ अभियुक्त को मिलना है।

दुर्भाग्य से, निचली अदालत ने इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों की अनदेखी करते हुए कानून को उलट दिया और यह माना कि बचाव अपीलार्थियों को दोषी ठहराने के अनुमान और अटकलों पर आधारित था और आरोपी को कोई लाभ प्रदान करने के लिए घटना के दो विचार नहीं हो सकते थे और यह सब, बिना किसी सबूत के चंद्र भानु, धप्पू राम और फैंटस को निर्दोषता प्रदान करते हुए। इस न्यायालय को मृत्युदंड की तो बात ही छोड़िए, दोषसिद्धि को बनाए रखना कठिन लगता है।

जिस तरह से मुकदमा आगे बढ़ा, जैसा कि ऊपर देखा गया, उससे यह प्रभाव पड़ता है कि अभियोजन पक्ष के गवाह अदालत कक्ष को एक दोस्ताना मैच के लिए एक खेल का मैदान मानते थे। दुर्भाग्य से ट्रायल कोर्ट ने रेफरी की भूमिका निभाते हुए रन को भुला दिया। यह न केवल स्वतंत्रता बल्कि एक नागरिक के जीवन को भी प्रभावित करने वाले मृत्युदंड और आजीवन कारावास के गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए न्याय के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कानूनी उक्ति का विध्वंस दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता था, कम से कम यह कहना दुर्भाग्यपूर्ण था।

हम संतुष्ट हैं कि वर्तमान मामला स्वर्गीय छोटे लाल प्रसाद के पुत्र राजेश प्रसाद पी डब्लू 7 के खिलाफ झूठी गवाही की कार्यवाही शुरू करने के लिए एक उपयुक्त मामला है।तदनुसार, हम निचली अदालत को कार्यवाही शुरू करने, कानून के अनुसार जांच करने और उचित आदेश पारित करने का निर्देश देते हैं।"

54. हमने ऐसा करने के लिए स्पष्ट कारण देते हुए दोषसिद्धि के निर्णय को पलटते हुए उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को उद्धृत किया है। हम यह भी देखते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पी डब्लू 1,3,4 और 7 के साक्ष्य को उनके उचित परिप्रेक्ष्य में समझने में विफल रहा है और आगे इस तथ्य को पहचानने में विफल रहा है कि पी डब्लू 7 ने/इसमें अपीलकर्ता ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया, हालांकि वह सूचक था और इसलिए, गलती से दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया और उनमें से दो को मौत की सजा और तीसरे आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हमारे विचार से, उच्च न्यायालय द्वारा त्वरित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश को उलट देना न्यायोचित था।

55. यह भी नोट किया गया है कि राज्य ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय और आदेश के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की है।

56. गवाहों के साक्ष्य की फिर से सराहना करने के बाद, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने दो अभियुक्तों, मुन्ना राम और महेंद्र राम को दोषी ठहराने और सजा सुनाने के फैसले को पलट दिया और उपेंद्र राम को आजीवन कारावास भुगतने के लिए अधिरोपित किया और इसके बजाय सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया।

57. इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने कहा है कि यह अपीलकर्ता के खिलाफ झूठी गवाही की कार्यवाही शुरू करने के लिए एक उपयुक्त मामला है (पीडब्लू7) यहां है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें अपीलकर्ता, जो मुखबिर था, उसने मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के मामले का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया और परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने आरोपी को बरी कर दिया। हालांकि, इन मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यह ध्यान में रखते हुए कि 10 मार्च, 2005 को हुई घटना में दो मौतें हुई थीं, जो उचित संदेह से परे साबित नहीं हुई हैं, हमने आक्षेपित निर्णय के केवल उस हिस्से को अलग रखा और निचली अदालत को झूठी गवाही की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया। इस में अपीलार्थी के खिलाफ हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के शेष निर्णय और आदेश की पुष्टि करते हैं।

58. अपीलों को केवल पूर्वोक्त सीमा तक ही आंशिक रूप से अनुज्ञात किया जाता है।

[एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति]

[बीआर गवई, न्यायमूर्ति]

[बी. वी. नागरत्न, न्यायमूर्ति]

नई दिल्ली

7 जनवरी, 2022

खण्डन (डिस्क्लेमर) :– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।